



2026:AHC:165764

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26621 वर्ष 2026

विवेक तिवारी @ विवेक कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्ष(गण)

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : मनीष कुमार

विपक्ष(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री शिव दत्त शुक्ला को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन अपराध संख्या 863 वर्ष 2025, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 137(2), 64(1), 115(2) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धाराओं 5(अ)(2), 5(ठ)/6 के अंतर्गत, थाना कोतवाली, जनपद देवरिया में पंजीकृत मामले में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

3. प्रारंभ में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचनादाता को नोटिस तामील करा दिया गया है।

4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट ढाई माह के विलंब के पश्चात दर्ज कराई गई है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धाराओं 180 एवं 183 के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। आगे प्रस्तुत किया गया है कि रेडियोलॉजिकल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



परीक्षण के अनुसार पीड़िता की आयु 18 वर्ष पाई गई है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की आयु 17 वर्ष पाई गई है, किंतु हाई स्कूल का कोई प्रमाण-पत्र अथवा उस विद्यालय का प्रमाण-पत्र, जिसमें पीड़िता ने सर्वप्रथम प्रवेश लिया था, उपलब्ध नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता ने चिकित्सीय-कानूनी परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक दिनांक 12.10.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसमें वह जमानत पर है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि आवेदक को जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके। तथापि, यह प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता गर्भवती है तथा कक्षा 10वीं के प्रमाण-पत्र के अनुसार उसकी आयु 17 वर्ष और रेडियोलॉजिकल परीक्षण के अनुसार 18 वर्ष है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो ढाई माह के विलंब के पश्चात दर्ज कराई गई है, में लगाए गए आरोप के अनुसार आवेदक द्वारा प्रथम सूचनादाता की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाना बताया गया है, तथापि पीड़िता बरामद कर ली गई है और पीड़िता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 180 के अंतर्गत अपने कथन में कहा है कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपना घर छोड़कर आवेदक के साथ बिहार गई थी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 183 के अंतर्गत अपने कथन में उसने कहा है कि दिनांक 3.7.2025 को वह आवेदक से मिलने गई थी और आवेदक ने उसे धमकी दी तथा गोरखपुर जाने के लिए कहा, जहाँ उसके बड़े भाई अनूप तिवारी और उसकी भाभी कविता देवी बस में बैठ गए और उसे बिहार ले गए, जहाँ आवेदक तथा सह-अभियुक्त अनूप तिवारी ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। अतः उसके कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रतीत होते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की आयु 17 वर्ष पाई गई है, किंतु हाई स्कूल का कोई प्रमाण-पत्र अथवा उस विद्यालय का प्रमाण-पत्र, जिसमें पीड़िता ने सर्वप्रथम प्रवेश लिया था, उपलब्ध नहीं है तथा रेडियोलॉजिकल परीक्षण के अनुसार उसकी आयु 18 वर्ष पाई गई है और पीड़िता ने चिकित्सीय-कानूनी परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है। आवेदक दिनांक 12.10.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसमें वह जमानत पर है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य एवं अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष दांडिक मामलों की भारी लंबितता को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जो 2025 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 3038 में प्रकाशित है, के निर्देश तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में दिए गए दिशा-निर्देश, जो 2024 एस.सी.सी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रकाशित हैं, को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

9. आवेदक- **विवेक तिवारी @ विवेक कुमार**, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित किए जाने में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा निवास संबंधी प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

12. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु विचारण न्यायालय, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजे।

7 अगस्त, 2026

अभिषेक

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।